नं. जेड-14014/1/2021-जीसी (ई-3010921)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011, दिनांक : 18.06.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मई, 2021 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के प्रमुख कार्यकलापों का मासिक सार- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को मई, 2021 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

अर्जुन राणा
(अर्जुन राणा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव।

माह मई, 2021 के दौरान भूमि संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों का मासिक सार

विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) का प्रायोगिक परीक्षण दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में माह मई, 2021 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

एक ही विषय पर लंबे समय से लंबित बहुत सारे आश्वासनों को पूरा करने के लिए, भूमि संसाधन विभाग ने दिनांक 17.05.2021 के अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से महा सचिव, लोक सभा और राज्य सभा से सचिवों की समिति द्वारा जांच की जानेवाली राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति संबंधी मसौदा रिपोर्ट/उसे राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद की बैठक में प्रस्तुत करने/राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बनाने से संबंधित संसदीय आश्वासनों को हटाने के बारे में शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

भूमि संसाधन विभाग ने कुछ विषयों जैसे (I) अनुपालन भार में कमी करने (ii) बजट कार्यान्वयन (iii) आत्मनिर्भर भारत और (iv) स्वायत्त निकायों आदि पर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2021 को आयोजित ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने 25.05.2021 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगमें विभाग की स्कीमों की समीक्षा की जिसमें विभाग के अधिकारियों द्वारा डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई में दो वर्षों की उपलब्धियों और अन्य संबंधित कार्यसूची बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण की गई। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई और मनरेगा के समामेलन तथा मसौदा ईएफ़सी में एफ़पीओ के घटक को शामिल किए जाने की इच्छा व्यक्त की।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत, आज की तारीख तक कुल 6382 परियोजनाओं {8214 (स्वीकृत)-1832 (राज्यों को हस्तांतरित)} में से 4796 परियोजनाओं को पूरा किया गया है। अब तक 2862 परियोजनाओं के एंड लाईन मूल्यांकन का कार्य पूरा किया गया है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

i. 6,00,689 ग्रामों के भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया।
ii. 4867 एसआरओ के रजिस्ट्रीकरण के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया।
iii. 1,10,06,447 भूकर मानचित्रों/एफ़एमबी/टिप्पनों के डिजिटीकरण के कार्य को पूरा किया गया।
iv. 3971 एसआरओ के साथ भूमि अभिलेखों के एकीकरण का कार्य पूरा किया गया।
v. 2304 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना का कार्य पूरा किया गया।

*****